Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language,
Online ISSN 2348-3083, SJ IMPACT FACTOR 2021: 7.278, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, AUG-SEPT, 2022, VOL-10/53
https://doi.org/10.21922/srjhsel.v10i53.11644

हाड़ौती क्षेत्र में डेयरी उद्योग की चुनौतियाँ : एक भौगोलिक विश्लेशण

बुद्धि प्रकाश, Ph. D

Assistant Professor in Geography, Jain Diwakar Kamala Mahavidyalaya, Kota, Rajasthan

Paper Received On: 25 SEPTEMBER 2022

Peer Reviewed On: 30 SEPTEMBER 2022

Published On: 1 OCTOBER 2022

Abstract

कृशि एवं पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है। स्वरोगार सृजन करने तथा आय में वृद्धि की दृश्टि से डेयरी उद्योग ग्रामीण एवं भाहरी क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। भारत में डेयरी उद्योग अंग्रेजों के शासनकाल में प्रारम्भ हुआ किन्तु दुग्ध सहकारिता की स्थापना के पश्चात् यहाँ एक नई क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। राजस्थान में अमूल पैटर्न की तर्ज़ पर ''राजस्थान को–ऑपटिव डेयरी फेडरेशन'' की देखरेख में दुग्ध संकलन एवं विपणन का कार्य प्रगति पर है।

राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में डेयरी उद्योग के विकास के समक्ष कई चुनौतियाँ अनुभव की गई है। जिनमें ग्रामीण एवं भाहरी क्षेत्र के पशुपालकों को दुग्ध उत्पादन एवं विपणन में कठिनाई तथा दुग्ध सहकारी संघों एवं निजी व्यापारियों को दूध संकलन एवं विक्रय में आ रही चुनौतियाँ प्रमुख हैं।

अध्ययन क्षेत्र में अनुभूत चुनौतियों के सन्दर्भ में समुचित समाधान विभिन्न स्तरों पर वांछित है। यद्यपि इस क्षेत्र में सरकार व सहकारिता स्तर पर प्रयास किए गये हैं तथापि डेयरी उद्योग को एक आधुनिक तकनीकि युक्त व समुन्नत बनाने के लिए कई ठोस प्रयास किये जाने की महती आव यकता है।

प्रमुख शब्द : *डेयरी उद्योग, आनन्द मॉडल, ऑपरेशन फ्लड़ आर.सी.डी.एफ., दुधारू पशु, सहकारिता, चरागाह भूमि एवं विपणन।*

Scholarly Research Journal's* is licensed Based on a work at *www.srjis.com

प्रस्तावना

कृशि प्राचीन काल से भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार रहा है। कृशि कार्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू पशुपालन एवं डेयरी उद्योग है। स्वरोजगार सृजन करने तथा आय में वृद्धि की दृश्टि से कृशि व पशुपालन के व्यापार क्षेत्र में डेयरी उद्योग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आरम्भिक समय में डेयरी का विकास केवल घरेलू आवशयकताओं की पूर्ति हेतु ही हुआ किन्तु कालान्तर में डेयरी उत्पादों की मांग एवं जनसंख्या की वृद्धि से यह वर्तमान में एक महत्वपूर्ण आर्थिक उपादन बन चुका है।

भारत में डेयरी उद्योग ब्रिटिश शासन काल में 1834 मे बॉम्बे (पिंजरापॉल) व 1889 में इलाहाबाद मिलिट्री डेयरी फॉर्म के रूप में शुरू हुआ। देश में स्वतंत्रता आंदोलन के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल

व मोरारजी देसाई जैसे नेताओं की प्रेरणा से बिचौलियों से मुक्ति पाने व डेयरी व्यवसाय की पूरी श्रृंखला पर नियन्त्रण पाने के उद्देश्य से सहकारी संघों का प्रादुर्भाव हुआ। वृहद पैमाने पर दुग्ध सहकारिता की स्थापना 1948 में गुजरात के खेड़ा जिले में की गई। इस दुग्ध सहकारिता द्वारा आयोजित डेयरी उद्योग से डेयरी विकास की एक नई भौली का जन्म हुआ जो **'आनन्द मॉडल'** (अमूल पेटर्न) के नाम से प्रसिद्ध हुई। सहकारिता के आधार पर भारत मे डेयरी विकास के लिए 1965 में **'राश्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड'** (NDDB) की स्थापना की गई। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने व सहकारी संघों को पर्याप्त दुग्ध आपूर्ति के लिए 1964–65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम (ICDP) चलाया गया। 1970 में राश्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया जिसे **'ऑपरेशन फ्लड'** नाम दिया गया। ऑपरेशन फ्लड के क्रियान्वयन के फलस्वरूप दुग्ध सहकारी संघों ने भारत में भवेत क्रान्ति के साथ सामाजिक व आर्थिक क्रान्ति को जन्म दिया तथा करोड़ों देशवासियों के जीवन–स्तर में बदलाव कर दिया।

राजस्थान में समुचित रूप से डेयरी उद्योग का प्रारम्भ 1967 में जयपुर डेयरी संयंत्र की स्थापना के साथ हुआ। राज्य में डेयरी विकास को गति देने के लिए 1973 में 'डेयरी

विभाग' तथा 1975 में 'डेयरी विकास निगम' की स्थापना की गई। राजस्थान में डेयरी विकास सम्बन्धी समस्त कार्यक्रम 'राजस्थान डेयरी कॉपरेटिव फेडरेशन' (RCDF) द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में सहकारिता के आधार पर डेयरी विकास 18 मई 1973 को प्रारम्भ हुआ जब कोटा भाहर में अमूल पद्धति के आधार पर 'कोटा जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ' की स्थापना की गई। संघ द्वारा 22 जून 1973 से गॉवों से दुग्ध संग्रहण का कार्य प्रारम्भ किया गया। डेयरी विकास का दूसरा चरण हाड़ौती में अप्रेल 1984 में ''कोटा डेयरी संयंत्र'' की कोटा भाहर में स्थापना से प्रारम्भ हुआ। इस संयंत्र की भराव/संग्रहण क्षमता 25 हजार लीटर प्रतिदिन थी जो माँग में निरन्तर वृद्धि से वर्तमान में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है।

उद्देश्य

इस शोध का उद्देश्य अध्ययन क्षेत्र मे विभिन्न स्तरों पर डेयरी उद्योग की चुनौतियों को पहचान कर उनका उपयुक्त समाधान प्रस्तुत करना है।

विधितंत्र

प्रस्तुत अध्ययन में व्यक्तिगत पर्यवेक्षण साक्षात्कार, प्रश्नावली द्वारा तथा कार्यालय कोटा–बून्दी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, कोटा प्रतिवेदन, जिला रूपरेखा व पशुपालन विभाग कोटा से आँकड़ों व सूचनाओं के संग्रहण उपरांत उनके विश्लेशण हेतु सारणीकरन करके आरेखीकरण किया गया है। सूचनाओं को धरातलीय सन्दर्भ में पुश्टि करने हेतु व्यक्तिगत रूप से वस्तु स्थिति के छायाचित्रों को समाहित किया गया है।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

शोध साहित्य की समीक्षा

डेयरी अध्ययन का आरम्भ वॉन थ्यूनेन (1826) के भूमि उपयोग अवस्थिति सिद्धान्त से प्रारम्भ हुआ। वर्तमान समय में डेयरी उद्योग विशय पर स्थानीय स्तर से लेकर अन्तर्राश्ट्रीय स्तर तक विभिन्न संगठनों द्वारा अध्ययन, विश्लेशण तथा अनुसंधान किए जा रहे हैं।

वी.एस.व्यास व के.एम.चौधरी (1970) ने कृशि आर्थिक शोध में मेहसाना के डेयरी व्यवसाय के आर्थिक स्वरूप को स्पश्ट किया है। मानमल जैन (1981) ने शोध ग्रन्थ में राजस्थान में सहकारिता के क्षेत्र में दुग्ध व डेयरी उत्पादों के उत्पादन का अध्ययन तथा इसकी समस्याओं की ओर ध्यान आकृश्ट किया। कुरियन वर्गीज़ (1984) ने दुधारु पशुओं के लिए वर्श भर पौश्टिक व हरे चारे की आपूर्ति व दुग्ध उत्पादन पर अनुसंधान किया। एम.के.खण्डेलवाल (1989) ने राजस्थान में डेयरी विकास का अध्ययन ग्रामीण नगरीय संसाधनों के विकास के सन्दर्भ में किया है। एम.सिंह (2002) ने अपने भाोध में राजस्थान में डेयरी पशुओं की वर्तमान स्थिति एवं भविश्य का विश्लेशण प्रस्तुत किया है। डी. के. शर्मा और एस. यादव (2021) ने बून्दी जिले में डेयरी विकास के द्वारा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरण पर शोध कार्य किया है।

अध्ययन क्षेत्र

राजस्थान का दक्षिणी–पूर्वी क्षेत्र एक विशिश्ट भौगोलिक इकाई है, जिसे हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसके अन्तर्गत बारां, बून्दी, झालावाड़ व कोटा जिलों को भाामिल किया गया है। हाड़ौती क्षेत्र $23^0$51′ उत्तरी अक्षांश से $25^0$51′ उत्तरी अक्षांश तथा $75^0$15′ पूर्वी देशान्तर से $77^0$25′ पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित है। इस क्षेत्र की उत्तर–पूर्व, पूर्व, दक्षिण एवं दक्षिण–पश्चिम सीमाओं पर स्थित क्रमशः पीपल्दा, मांगरोल, किशनगंज, शाहबाद, छबड़ा, छीपाबड़ौद, मनोहर थाना, अकलेरा, झालरापाटन, पिड़ावा गंगधार, पचपहाड़ व रामगंजमंडी तहसीलों की सीमा मध्य प्रदेश से मिलती है। उत्तर में स्थित पीपल्दा व इन्द्रगढ़ तहसीलें राज्य के सवाईमाधोपुर जिले की सीमा से, नैनवा तहसील टोंक जिले से, हिण्डोली तहसील भीलवाड़ा जिले की सीमा से मिलती है। पश्चिम की ओर बून्दी व लाड़पुरा तहसीलों की सीमा चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा से मिलती है। यह सम्पूर्ण क्षेत्र 24204.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। हाड़ौती की कुल जनसंख्या (जनगणना 2011 के अनुसार) 5695804 है। जिसमें ग्रामीण जनसंख्या 3812994 व शहरी जनसंख्या 1882810 है। यहाँ की कुल पशुधन संख्या 3.43 मिलियन है। जिसमें से दुधारू पशुओं की संख्या लगभग 2.3 मिलियन है जो कि राजस्थान के दुधारू पशुधन का 8.3 प्रतिशत है।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

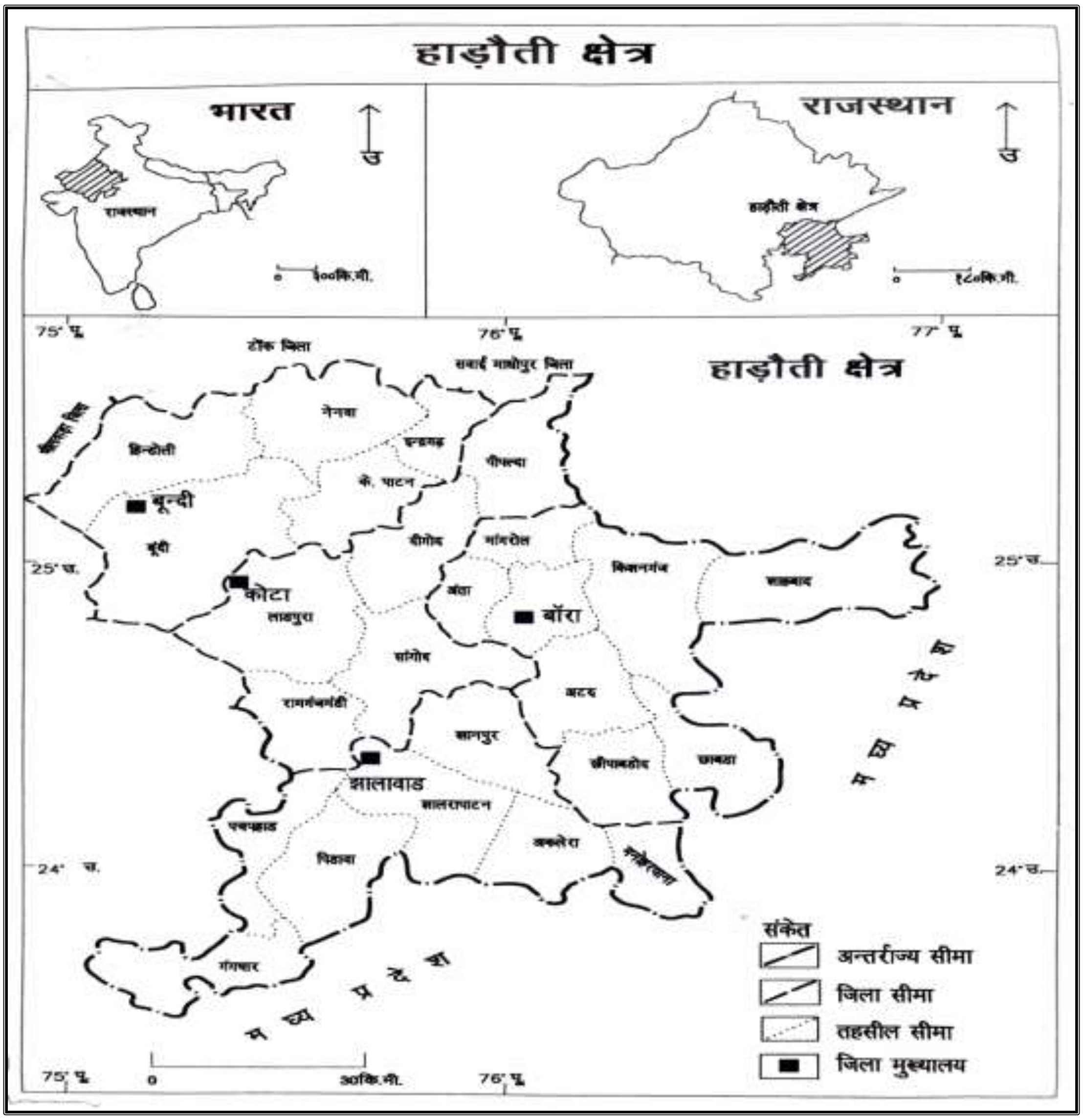

डेयरी उद्योग की चुनौतियाँ

कोटा–बून्दी दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड़, कोटा में वर्तमान में कुल 707 प्राथमिक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियाँ पंजीकृत है। इन पंजीकृत सहकारी समितियों के अलावा 130 प्रस्तावित दुग्ध उत्पादन सम्बन्धी समितियाँ कार्यरत हैं। ग्रामीण दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों का आनन्द पद्धति पर गठन कराके दुग्ध संकलित किया जाता है। गत वर्श में संघ द्वारा औसतन 91832 लीटर दूध प्रतिदिन संकलित कर 1405 विपणन केन्द्रों पर औसतन 65400 लीटर प्रतिदिन की बिक्री की गई है। झालावाड़–बारां जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड़, झालावाड़ वर्श 2007 से क्षेत्र में दुग्ध उत्पादकों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रयत्नशील है। वर्तमान में संस्था द्वारा कुल 95 कार्य ील पंजीकृत एवं 74 प्रस्तावित दुग्ध समितियों की महिला सदस्यों सहित लगभग 5000 पशु पालक सदस्यों से औसतन 20 हजार लीटर दुग्ध प्रतिदिन संकलित किया जा रहा है। बारां जिले में डेयरी प्रोसेसिंग प्लांट नहीं होने से झालावाड़ डेयरी पर दूध भेजा जाता है। यहाँ डेयरी उद्योग व्यापक स्तर पर वृहद व्यवसाय का निर्णय नहीं ले पाये जाने की कई चुनौतियाँ है।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश में सहकारिता एवं निजी क्षेत्र में डेयरी उद्योग के विकास की प्रबल संभावना है। क्योंकि यहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल होने के साथ ही विस्तृत बाजार (माँग क्षेत्र) उपलब्ध है, किन्तु यहाँ इसकी प्रगति एवं वर्तमान प्रतिरूप के समक्ष कई चुनौतियाँ हैं, जिनको पहचानना और उनका समाधान खोजना अत्याव यक है। अध्ययन क्षेत्र की डेयरी उद्योग की चुनौतियों को चिन्हित कर विभिन्न स्तरों पर भौगोलिक विश्लेशण किया गया है।

हाड़ौती क्षेत्र में निम्न स्तरों पर डेयरी उद्योग की चुनौतियों को पहचाना गया है–

1. ग्रामीण स्तर पर पशुपालकों की चुनौतियाँ
2. शहरी क्षेत्र में पशुपालकों की चुनौतियाँ
3. सहकारिता के क्षेत्र में डेयरी उद्योग की चुनौतियाँ
4. निजी–क्षेत्र में डेयरी व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों की चुनौतियाँ
5. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के स्तर पर चुनौतियाँ
6. ग्रामीण एवं शहरी उपभोक्ताओं के स्तर पर चुनौतियाँ

1. ग्रामीण स्तर पर पशुपालकों की चुनौतियाँ

(क) चरागाह भूमि की कमी

पालतू पशुओं के स्वतंत्र रूप से चरने के लिए प्रत्येक ग्राम–क्षेत्र में चरागाह भूमि आवंटित होती है परन्तु सैद्धान्तिक रूप से यह केवल अब सरकारी दस्तावेजों में ही सिमट कर रह गया है। इस भूमि पर वास्तव में अतिक्रमणों की भरमार है। पशुओं को चराने के लिए अब कोई जगह नहीं बच पायी है।

तालिका – 01: चरागाह भूमि के क्षेत्रफल/स्थिति में आई कमी के सन्दर्भ में प्राप्त उत्तरों का विश्लेशण

क्र.सं.	जिला	सहमत		असहमत		अनिश्चित		कुल उत्तरदाता
		सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	
1	बारां	24	96	0	0	1	4	25
2	बून्दी	22	88	0	0	3	12	25
3	झालावाड़	21	84	0	0	4	16	25
4	कोटा	19	76	0	0	6	24	25
	योग	86	86	0	0	14	14	100

स्त्रोत – प्रश्नावली द्वारा एकत्रित आंकड़ें।

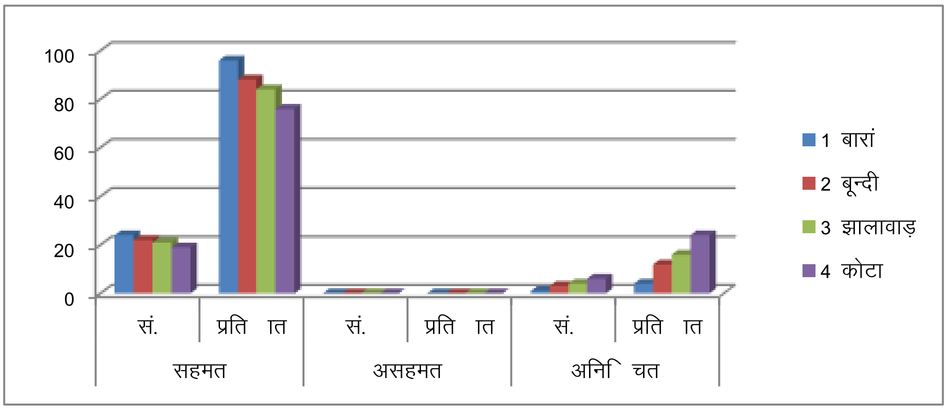

आरेख–01: चरागाह भूमि के क्षेत्रफल/स्थिति में आई कमी के सन्दर्भ में प्राप्त उत्तरों का विश्लेशण

प्राथमिक स्रोत से प्राप्त समंकों से ज्ञात होता है कि चरागाह भूमि में लगातार कमी आती जा रही है। जिसमें भूमाफिया द्वारा अतिक्रमण तथा सरकार द्वारा अनियोजित रुप से भू—रूपान्तरण किया जाना पाया गया है। बारां जिले से प्राप्त आंकड़ों से स्पश्ट है कि यहाँ 96 प्रतिशत उत्तरदाता इस तथ्य से सहमत है कि चरागाह भूमि में कमी हो रही है। बून्दी व झालावाड़ में क्रमशः 88 व 84 प्रतिशत सदस्यों ने स्वीकार किया कि क्षेत्र में पशुओं के लिए चरागाह क्षेत्र लगातार घटते जा रहे है। कोटा जिले में सहमति का प्रतिशत 76 पाया गया है।

(ख) पशुपालन में वैज्ञानिक तरीकों का अभाव

ग्रामीण क्षेत्र में आज भी परम्परागत ढंग से पशुपालन किया जा रहा है जो कि अनार्थिक है। वैज्ञानिक ढंग से किया जाने वाला पशुपालन लाभदायक हो सकता है। हाड़ौती ग्रामीण अंचल में देसी नस्ल वाले पशुओं को प्राथमिकता दी जाती है। इनकी दुग्ध उत्पादक क्षमता भी कम होती है। संकर नस्ल के पशुओं को पालने में वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी कई भ्रांतियाँ है। परम्परागत ढ़ंग से किये जाने वाले पशुपालन में सभी पशुओं को एक साथ बांधा जाता है, एक ही प्रकार का चारा डाला जाता है, अस्वच्छ पर्यावास में किसी एक पशु के बीमार होने पर सभी पशु बीमार हो जाते हैं। वर्तमान में लम्पी रोग के प्रसार का एक कारण यह भी रहा है।

वैज्ञानिक तरीके नहीं अपनाने का एक बड़ा कारण प ाुपालनों की निर्धनता भी है। झालावाड़ जिले के अकलेरा, मनोहरथाना तथा बून्दी जिले की नैनवां तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में पशुपालकों के लिए डेयरी उत्पाद केवल आजीविका का निर्वहन मात्र है। वे केवल घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति ही कर पाते हैं। बारां जिले की अंता व मांगरोल तहसील में पशुओं की उन्नत किस्म में लगातार गिरावट आ रही है।

2. नगरीय क्षेत्र में पशुपालकों की चुनौतियाँ

(क) चारा भण्डारण की कठिनाई

बारां, बून्दी, झालावाड़ व कोटा जिला मुख्यालय या दूध व इसके उप—उत्पाद की मांग अधिक होने के कारण यहाँ पशुपालक नालों/उद्यानों व कच्ची बस्ती के निकट अस्थाई आवास बना लेते हैं और वहीं पशुपालन कार्य करते हैं। इन स्थानों पर पशुआहार (भूसा) के संग्रहण की बड़ी कठिनाई रहती है। व्यावहारिक रूप से यह भी पाया गया कि पशुपालक अपने पशुओं के लिए पूरे वर्श के उपयोग निमित्त भूसा/चारा नहीं खरीद सकते, आर्थिक स्थिति कमजोर होने से वे दैनिक, साप्ताहिक या मासिक पशुआहार ही संग्रह/क्रय कर पाते है।

(ख) पशुओं से प्राप्त अपशिश्ट पदार्थ (गोबर/मूत्र) का उचित दर पर विपणन नहीं होना

भाहरी क्षेत्र में जीवन भौली के अनुसार अपेक्षाकृत अधिक आय के स्त्रोत की आवश्यकता होती है। पशुपालकों को परिवार के अतिरिक्त पशुओं का भी पालन करना होता है। सारे पशु एक समय में दुधारू नहीं होते हैं जबकि हर पशु पर आहार की दृश्टि से समान खर्चा होता है। एक तरह से जो पशु दूध नहीं दे रहे हैं, वे पशुपालक पर भार स्वरूप हो जाते हैं।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

यदि उचित दर पर पशुओं के अपशिश्ट (गोबर/मूत्र) का विपणन हो जाए तो पशुपालकों का आर्थिक भार कम हो सकता है परन्तु वर्तमान में ऐसी व्यवस्था का अभाव पाया गया है। अध्ययन क्षेत्र के बारां, बून्दी, झालावाड़ को छोड़कर केवल कोटा में देवनारायण योजना के अन्तर्गत ही गोबर क्रय/विक्रय की नई भुरुआत की गई है।

तालिका–02:पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग

जिला/ शहर	घरेलू ईंधन		गोबर रूप में विक्रय		खाद रूप में विक्रय		कुल उत्तरदाता
	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत	
बारां	5	20	0	0	20	80	25
बून्दी	4	16	0	0	21	84	25
झालावाड़	5	20	0	0	20	80	25
देव नारायण योजनावासी (कोटा)	.	.	15	100	.	.	15
शेश भाहरवासी (कोटा)	1	10	15	100	9	90	10
योग	15	15	15	15	70	70	100

स्त्रोत – प्रश्नावली द्वारा एकत्रित।

उक्त तालिका से स्पश्ट है कि झालावाड़ व बारां जिले के पशुपालन कुल गोबर उत्पाद का 80 प्रतिशत भाग खाद रूप में विक्रय करते हैं तथा ईंधन (उपले) में 20 प्रतिशत उत्पाद का उपयोग करते हैं। बून्दी जिले में खाद रूप में लगभग 84 प्रतिशत विक्रय करते हुए, 16 प्रतिशत गोबर का ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। परन्तु कोटा जिले में देवनारायण योजनान्तर्गत आवासी पशुपालक अपने गोबर उत्पाद का 100 प्रतिशत भाग गोबर गैस प्लांट हेतु विक्रय कर रहे हैं, भोश भाहर में आवासी पशुपालन अपने गोबर का 90 प्रतिशत भाग खाद रूप में विक्रय तथा 10 प्रतिशत गोबर का उपयोग ईंधन रूप में कर रहे हैं।

पशुपालक पशुओं के मूत्र का कोई उपयोग वर्तमान में नहीं कर पा रहे हैं।

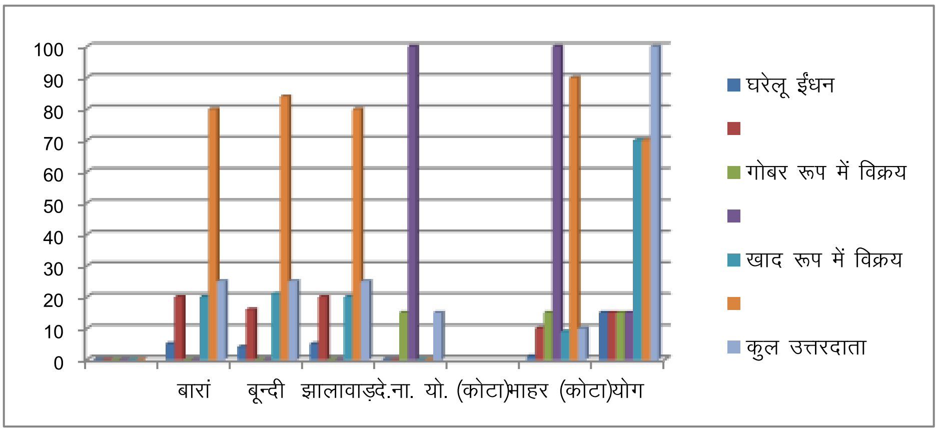

आरेख – 02:पशुओं से प्राप्त गोबर का उपयोग

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

(ग) दुग्ध उत्पादन व विपणन में मौसमी परिवर्तन

दुग्ध उत्पादन में तापमान का बहुत प्रभाव पड़ता है। गर्मी के मौसम में दुग्ध का उत्पादन कम हो जाता है। हाड़ौती क्षेत्र में मई—जून में पशुओं की दूध देने की क्षमता में कमी आने के कारण बड़े भाहरों में दूध की घरेलू मांग को ही पूरा करना मुश्किल होता है। दुग्ध विपणन की दृश्टि से कोटा भाहर का विशेश स्थान है। यहाँ कोचिंग का विश्वस्तरीय केन्द्र है। छात्र मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई/तैयारी के लिए पूरे वर्श यहाँ रहते है, यद्यपि आंशिक आवागमन चलता रहता है फिर भी अनुमानतः 2 से 2.25 लाख विद्यार्थी यहाँ आते हैं। यह संख्या यहाँ के मूल विद्यार्थियों के अतिरिक्त है अर्थात् मूल जनसंख्या में 2 से 2.25 लाख की वृद्धि होती है। यह संख्या प्रतिवर्श 10 प्रति ात की दर से निश्चित रूप से बढ़ेगी। इसी अनुपात में दुग्ध व उत्पादों की मांग भी बढ़ती है। इसके विपणन में कठिनाई आना स्वाभाविक है। यहाँ मौसमी परिवर्तन जलवायु से नहीं, अपितु छात्रों के अध्ययन के समयान्तराल से है। मांग में वृद्धि की आपूर्ति चुनौती बनकर मिलावट को प्रोत्साहन देती है।

न्यूनतम 280 ग्राम प्रति व्यक्ति भी दूध का उपयोग माने तो यह 63000 लीटर दूध प्रतिदिन की मांग होगी, जो कोटा भाहर की मांग के अतिरिक्त है। यह अपने आप में बड़ी चुनौती है।

3. सहकारिता के क्षेत्र में डेयरी उद्योग की चुनौतियाँ

सहकारी संगठन में विभिन्न क्षेत्र व विभिन्न प्रकार के विचारों के लोगों की साझेदारी होती है। इनमें कई स्तरों पर चुनौतियाँ होना स्वाभाविक है। प्राथमिक स्तर पर ग्राम दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति संचालित होती है। वहाँ कम शिक्षित लोगों के साथ कारोबार चलता है। यहाँ संसाधनों की अल्पता होती है। दूध ऐसा पदार्थ है, जो लापरवाही से खराब हो जाता है, जिसका नुकसान समिति के सदस्यों को भुगतना पड़ता है।

जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ को कई स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ग्राम समिति स्तर पर दूध की जाँच के समय मिलावट का पता चलने पर आपसी तनातनी का वातावरण हो जाता है। परिवहन के तीव्रगामी व अधुनातम तकनीकी युक्त यातायात साधनों का अभाव प्रमुख चुनौती है। हाड़ौती क्षेत्र में दुग्ध संकलन मार्गों की स्थिति को देखते हुए लम्बे निर्धारित मार्ग होना भी एक कठिनाई है, इससे दुग्ध की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इन निर्धारित मार्गों को बार—बार बदलना, परिवहनकर्ता/उत्पादककर्ता दोनों के लिए एक चुनौती है। संघ द्वारा भुगतान प्रक्रिया में त्वरितता व पारदर्शिता नहीं पायी गई।

हाड़ौती क्षेत्र में ग्राम दुग्ध उत्पादन समिति के पशुपालकों में वैज्ञानिक सोच व दृश्टिकोण का व्यावहारिक अनुभव कम है। इससे उन्हें आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न होती है। डेयरी उद्योग में ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की भागीदारी भी आव यक है। इनके अदृश्य श्रम को उपयुक्त पहचान नहीं मिल पा रही है। समग्रतः महिलाओं को उचित सामाजिक सम्मान व आथिक स्वावलम्बन का अभाव महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक चुनौती है।

4. निजी क्षेत्र में उत्पादक, विक्रेता व उपभोक्ता स्तर पर चुनौतियाँ

हाड़ौती के ग्रामीण अंचल के उत्पादकों व विक्रेताओं के पास अपने दुग्ध उत्पादों को सुरक्षित व संरक्षित करने के लिए आधुनिक अवशीतन संयंत्रों का अभाव है। जब उत्पादों व विक्रेताओं को अपनी लागत का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता तो वे मिलावट का सहारा लेते हैं। ऐसी अवस्था में निजी स्तर पर जाँच की प्रक्रिया का भी अभाव देखा जाता है। उपभोक्ता स्तर पर दूध की गुणवत्ता व भाुद्धता की पहचान करना, आम–आदमी के स्तर पर संभव नहीं हो पाता, यह बहुत बड़ी कठिनाई है। घरेलू आपूर्ति में ऊँचे दाम पर भी निश्चित समय पर शुद्ध व गुणवत्ता युक्त दुग्ध की उपलब्धता कसौटी पर है। डेयरी उद्योग के समुचित विकास के लिए उक्त चुनौतियों का उचित और व्यवहारिक समाधान बहुत आव यक है।

डेयरी उद्योग के विकास हेतु अनुभूत चुनौतियों के सन्दर्भ में समाधान

(i) स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर पालिका व नगर निगम) द्वारा समय–समय पर क्षेत्र की चरागाह भूमि को मुक्त कराने हेतु अतिक्रमण हटाने के प्रभावी अभियान चलाये जाने वांछित हैं।

(ii) वैज्ञानिक विधि से पशुपालन के लिए गौ संवर्धन योजनाओं में नस्ल सुधार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, पौश्टिक आहार रख–रखाव आदि के लिए विशेश प्रशिक्षण व जागरूकता शिविर संगोश्ठी व परिचर्चाओं का आयोजन जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ/जिला कृशि विज्ञान केन्द्रों द्वारा किया जाना उचित होगा।

(iii) भाहरी क्षेत्रों में अनाज भण्डारण के वेयर–हाउस की तर्ज पर सूखा चारा भण्डारण की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

(iv) पशुओं से अपशिश्ट के रूप में गोबर व मूत्र प्राप्त होता है। इसका समुचित उपयोग व विपणन आवश्यक है। गोबर के लिए **''वेस्ट टू वेल्थ''** के विजन की ओर ध्यान देते हुए एक बड़ा गोबर गैस प्लांट स्थापित किया जाना चाहिए इससे पशु पालकों को आर्थिक सम्बल मिलेगा तथा दूसरी ओर सस्ती और प्रदूशण रहित ईंधन गैस उपलब्ध हो पायेगी। इसका भाहरी/ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में घरेलू ईधन के अलावा, परिवहन साधनों में भी उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में कोटा संभाग में पशुओं के मूत्र का कोई आर्थिक उपयोग नहीं हो रहा है। इसका सामयिक संकलन कर आयुर्वेदिक दवाओं के रूप में यदि उपयोग किया जाए, तो उत्पादकों को इससे आर्थिक सम्बल भी प्राप्त होगा। सहकारी व सरकारी स्तर पर प्रयास आव यक है। समाधान की दिशा में राजस्थान सरकार भी कुछ विशिश्ट योजनाएँ लाकर गोबर के उपयोग व विपणन के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठा सकती है। छत्तीस गढ़ सरकार द्वारा ''गोबर न्याय योजना'' संचालित की जा रही है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी ''गोबर–धन'' योजना का इन्दौर (म.प्र.) में दिनांक 19 फरवरी 2022 को शुभारंभ किया

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

गया है। इन योजनाओं में पशुपालकों से गोबर क्रय कर गोबर–धन प्लांट लगाकर सी.एन.जी. का उत्पादन किया जा रहा है।

इससे ग्रामीण व भाहरी पश ुपालकों को प्रत्यक्ष रुप से विश ोश कर महिलाओं की पारिवारिकों व आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और उन्नत हुई है।

(v) गोबर का अतिरिक्त उपयोग– खाद के रूप में जो गोबर उपयोग में आ रहा है, उसका एक विकल्प भी है, इस गोबर से ऊपले व (काश्ठ रूप) कृत्रिम लकड़ी यदि बनाती जाए तो अन्त्येश्टि के अवसर पर प्रयुक्त किया जा सकता है जो वृक्ष व पर्यावरण बचाओं अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इससें रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी व उत्पादक को आर्थिक लाभ होगा।

(vi) कोटा भाहर में देवनारायण योजनान्तर्गत पशुपालकों को कोटा के ही उपनगरीय क्षेत्र में एक निश्चित स्थान (नन्द ग्राम) पर स्वयं का आवासीय भवन एवं पशुओं के लिए आवास स्थल उपलब्ध कराये गये हैं। राजस्थान सरकार का यह प्रयास प्रशंसनीय है। परन्तु इस योजना का विस्तार तहसील स्तर पर भी किया जाना अपेक्षित है। ताकि ग्रामीण पशुपालक भी लाभांवित हो सकें।

(vii) कोटा जैसे भाहर में जहाँ कोचिंग के लिए प्रतिवर्श 2 से 2.50 लाख विद्यार्थी आते हैं उनके लिए दूध की अतिरिक्त मांग अचानक बढ़ जाती है। इसकी पूर्ति के लिए अन्य समीप के जिलों की डेयरी से दूध की आपूर्ति यदि तत्परता व आधुनिक परिवहन साधनों से करवाई जाए तो विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त, स्वास्थवर्द्धक दूध उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सकेगा।

(viii) दूध की विपणन की दृश्टि से तीव्रगामी व अधुनातम (नवीन) तकनीकीयुक्त परिवहन के साधनों का उपयोग समय की मांग है, ताकि उत्पाद तत्परता व गुणवत्ता के साथ दूरस्थ स्थानों पर पहुँच सकेंगे।

(ix) डेयरी उद्योग में महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की संख्या में वृद्धि कर व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए, इस हेतु सहकारी संघ के माध्यम से महिलाओं को प्रोत्साहित व प्रशिक्षित किया जाए। इससे उनका सामाजिक सम्मान और आर्थिक स्वावलम्बन बढ़ेगा, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा नें मील का पत्थर साबित होगा।

(x) बारां जिले में दुग्ध उत्पादकों के आर्थिक लाभ हेतु बारां भाहर में दुग्ध सहकारी संघ व डेयरी प्लांट (दुग्ध संग्रहण एवं विक्रय केन्द्र) भीघ्र ही स्थापित किया जाना चाहिए।

(xi) डेयरी विकास के लिए निजी क्षेत्र के उत्पादकों/विक्रेताओं को भी संगठित करने की आव यकता है ताकि विक्रय दर, जाँच, गुणवत्ता नियंत्रण को प्रभावी बनाया जा सके। निजी क्षेत्र में भी लघु वित्त ऋण व बीमा प्रक्रिया को सरल व सुलभ बनाया जाए ताकि उपनगरीय क्षेत्रों में भी स्वरोजगार सृजन हो पाये और ग्रामीण युवाओं को शहर की ओर पलायन से रोका जा सके।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language

कोटा भाहर के सुभाश नगर
नाले के पास पशुपालन

कोटा भाहर के सुभाश
नगर नाले के
पास पशुपालन

1. अस्वच्छ पर्यावास में पशुपालन

2. अस्वच्छ पर्यावास में पशुपालन

पशुओं के लिए सूखा चारा विक्रय स्थल
(देवनारयण योजना के निकट, कोटा)

निश्कर्श

डेयरी उद्योग में ही नहीं, वरन किसी भी क्षेत्र में आई चुनौतियों के समाधान से सरकारी मशीनरी के साथ–साथ, जन सहभागिता व राजनैतिक इच्छा शक्ति की प्रबलता महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों पर चुनौतियों का समाधान करने हेतु इसकी महती आव यकता है। स्थानीय से केन्द्रीकृत एक समग्र ढांचा बनाकर उचित रूप से योजनाओं का क्रियान्वयन किये जाने पर हाड़ौती क्षेत्र में डेयरी उद्योग समेकित रूप में विकसित होकर क्षेत्र में जनजीवन के विकास के नये आयाम स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगा।

सन्दर्भ सूची

Thunen, V. (1826), "Der Solierte Steat in Berichang and Land Wirstschaft".

2. *Govt. of India (1974-1979), 'Planning Commission Draft 5th, 5Year Plan I,II, P.No. 27-28*

Vyas, V.S. and Choudry, K.M. (1970), "Economics of Dairy Family in Meha Sana" Agro Economic Research Centre Vallabh Vidhya Nagar, P.120

Jain, Manmal (1981), "Growth Pattern of Dairy Sub. Sector in Rajasthan", Himalaya Published House, New Delhi.

Karien, V. (1984), "Feedly and Mangement of Dairy Cattle " Dairy Guide, P.P. 39-44

Khandelwal, M.K. (1989), "Dairy Industry in Rajasthan, Geography Deporatment, University of Rajasthan. Jaipur (Unpublished Thesis).

Purohit, S.B. (1992) 'Dairy Devlopment in Rajasthan' Unpublised Thesis University of Raj. Jaipur. P.No.19-22

घोस, अरविन्द (जनवरी 2002), 'ग्रामीण पुर्ननिर्माण की ओर बढ़ते कदम' योजना, पृ.सं. 2

कुरियन, बी. (अगस्त 2004), 'दुग्ध उत्पादन ग्रामीण विकास का एक साधन', योजना, पृ.सं. 11

बंसल, अनिल (मार्च 2004), 'ग्रामीण और कृशि विकास में बदलेगी अर्थव्यवस्था', कुरूक्षेत्र, पृ.सं. 7

Nandwana G. (2005), 'Agriculture and Socio-Economic Transformation: A case Study of Bundi District (Unpublished Thesis)

भारत की जनगणना 2011, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान, जयपुर।

पशुगणना–2019, जिला सांख्यिकी रुपरेखा, बारां, बून्दी, झालावाड़, कोटा।

S. Yadav and Z. Khan, (2020), 'Research Column Intra-Regional Disparities in Hadoti Region A Geographical Analys in Research Column.

D. Sharma and S.Yadav (2021), "Socio Ecomomic Transformation by Dairy Devolepment in Bundi District, International Innovative Research Science Engineering and technologyTechnol, V-10, No. 7, P.No.- 9228

Sharma, D.K. and Yadav, S. (July-2021), "Socio-Economic Transformation by Dairy Develoment in Bundi District Raj." International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology.

Annual Report (2021), "Aam Sabh, Kota Jila", Dugdhh Utpadak Sahkari Sangh, Kota.

कार्यालय, कोटा–बून्दी जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, कोटा (राज.)

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language